

(3) G. S. R. 747 published in Gazette of India dated the 17th April, 1968 rescinding Bihar Government's Order No. 21807-S. C. dated the 1st November, 1966, prohibiting export of pulses from Bihar. [Placed in Library. See No. LT-1021/68]

**Notification under Industrial Disputes Act and Employees' State Insurance (Control) Second Amendment Rules**

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI S. C. JAMIR) : I beg to lay on the Table :

- (1) (i) A copy of Notification No. 30-I.R./IR/IA/1(A)/64-Pt. published in the Calcutta Gazette dated the 25th January, 1968 adding certain industries to the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947, under sub-section (3) of section 40 of the said Act, read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 20th February, 1968, issued by the President in relation to the State of West Bengal.
- (ii) A statement showing reasons for delay in laying the above Notification. [Placed in Library. See No. LT-1022/68].
- (2) A copy of the Employees' State Insurance (Control) Second Amendment Rules, 1968 published in Notification No. G. S. R. 677 in Gazette of India dated the 6th April, 1968, under sub-section (4) of section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948. [Placed in Library. See No. LT-1023/68].

-----

**ESTIMATES COMMITTEE**

**Fifty-fourth Report**

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal) : I beg to present the Fifty-fourth Report of the Estimates Committee on action taken by Government on the recommendations contained in the Hundred and Second Report of the Estimates Committee (Third Lok Sabha) on the Ministry of Education—University Grants Commission,

-----

**COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS**

**Sixteenth, Seventeenth and Eighteenth Reports**

SHRI D. N. TIWARY (Gopalgani) : I beg to present the following Reports of the Committee on Public Undertakings :

(1) Sixteenth Report on action taken by Government on the recommendations contained in the Thirty-ninth Report of the Committee on Public Undertakings (Third Lok Sabha) on Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi.

(2) Seventeenth Report on action taken by Government on the recommendations contained in the Fifteenth Report of the Public Accounts Committee (Third Lok Sabha) regarding Audit Report on the Accounts of Damodar Valley Corporation for the year 1961-62.

(3) Eighteenth Report on action taken by Government on the recommendations contained in the Third Report of the Committee on Public Undertakings (Third Lok Sabha) on the Shipping Corporation of India Limited.

-----

12 30 hrs.

**QUESTIONS ON STATEMENT MADE BY MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE ON 22ND APRIL 1968**  
**RE APEEJAY SHIPPING COMPANY**

श्री मधु लिमये (मुं गेर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो सवाल अब मैं पूछ रहा हूँ यह खाद्य मन्त्री श्री जगजीवन राम के द्वारा टामस साहब को वापिस बुलाने के सम्बन्ध में मेरा जो सवाल था उसमें से उत्पन्न हुआ है। उस का उन्होंने जो उस समय जवाब दिया था, उस जवाब को जो वह 22 अप्रैल को दुस्त कर रहे हैं। वह इनके उस 22 अप्रैल वाले बयान को लेकर है मैं सवाल पूछना चाहता हूँ।

सब से पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय ने अपने उस 22 अप्रैल वाले वक्तव्य में जो अपने पहले उत्तर को शुद्ध किया है लेकिन उसे उन्होंने पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं किया है। इस में और भी दो गल-

## [श्री मधु लिमये]

तियां रह गयी हैं। उन की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

इस के बारे में आप के अध्यक्षीय निर्देश 115 के तहत मैंने अपना बयान दिया, सब से पहले दिया था फिर भी आप ने उस को स्वीकारना उचित नहीं समझा। उस के बारे में मुझे नहीं कहना है लेकिन अब वह शुद्धिकरण जो करना चाहते हैं वह पूरा करें। जैसे कि श्री जगजीवन राम ने उस दिन कहा था। यह 11 अप्रैल की कार्यवाही है। पहले श्री शिन्दे ने कहा :

"I think the Minister has a right to call for any paper and there was nothing unusual as has been mentioned by the hon. Member."

टामस साहब की जो फ़ाइल मंगवाई तो उस में कोई अनयुजबल या असाधारण बात नहीं है। आगे जगजीवन राम जी उसी दिन कहते हैं :

"There is nothing unusual in it."

अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन को इस बात का पता नहीं है कि प्रधान मन्त्री जी ने 626 तारांकित प्रश्न का 18 मार्च को मुझे जो उत्तर दिया है उस में यह साफ़ लिखा हुआ है :

"The normal procedure prescribed is for files and papers coming up for decision to travel from the low to the higher level and reach the Minister through a Joint Secretary/Secretary. In specific cases a Deputy Secretary may also deal direct with the Minister."

इस में नारमल प्रोसीजर दे दिया गया है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ही फाइल मिनिसटर के सामने रख सकते हैं। यह साधारण प्रक्रिया है। लेकिन उन्होंने आगे कहा है :

However instructions provide for level-jumping.

अगर असाधारण हो तो मिनिसटर सीधे भी मंगा सकते हैं विशेष केसेज में वह ऐसा कर

सकते हैं। यह सारी असाधारण प्रक्रिया है इसलिए मन्त्री महोदय का यह भी उत्तर ठीक नहीं था। शायद उनको पता नहीं था कि प्रधान मन्त्री ने क्या जवाब दिया है? हां यह बात सही है कि साधारण रूप में ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ही फाइल रखते हैं लेकिन विशेष स्थिति में उसे वह सीधे भी मंगा सकते हैं। अब जब विशेष स्थिति है तो विशेष जिम्मेदारी भी आ जाती है।

दूसरे उन्होंने अपने 22 अप्रैल के स्टेटमेंट में कहा है :

"These enquiries have now revealed that hon. Member, Shri Madhu Limaye, wrote a letter dated the 16th February, 1968 to the Prime Minister, in which he had *inter alia* asked whether the Prime Minister would consider recalling Shri Thomas from Australia."

अब मेरे पास पत्र तो नहीं है लेकिन मुझे निश्चित रूप से यह याद है कि मैंने उन से यह नहीं पूछा कि क्या आप इस पर विचार कर सकते हैं कि टामस साहब को बुलाया जाय? मैं ने स्पष्ट मांग की थी कि उन को बुलाया जाय क्योंकि उन्होंने अपनी यह एपीजे शिपिंग कम्पनी की असाधारण तरीके से फाइल देखने के पश्चात भी कोई कुछ नहीं किया है इसलिए उनको रिकॉल किया जाय।

अब सब से बड़ी बात जो उस में से निकलती है उस का जवाब माननीय जगजीवन राम नहीं दे सकते हैं उस का जवाब तो इन्दिरा जी को ही देना पड़ेगा। आप सावधानी से उन का बयान पढ़िये। उन्होंने यह लिखा है :

"An extract from the said letter (*i.e.* my letter) regarding the recall of Shri Thomas was not sent either to the Ministry of External Affairs or the Department of Food as the facts of the case had first to be ascertained from my Department (*i.e.* the Food Department) and only then would the Prime Minister have been in a position to examine whether there was a *prima* 1

case for considering the suggestion for recall. The Prime Minister's Secretariat accordingly sent on 9th March, 1968 for our comments extracts from the said letter of Shri Madhu Limaye relating to the Department of Food. Our comments were only duly sent to the Prime Minister on the 30th March, 1968."

अब मेरा सवाल 11 अप्रैल को आता है। 30 मार्च को इन को खाद्य मन्त्रालय के सारे कर्मियों और तथ्य मिल जाते हैं। अब 30 मार्च और 11 अप्रैल के बीच में इन को सारी स्थिति पर विचार करके रिक्वायर्स के बारे में अपना निर्णय करना चाहिए था और उस की इच्छिता जगजीवन राम जी को देनी चाहिए थी। लेकिन आप देखिये इन की मिनिस्ट्री पूछती है ऐक्सटरनल एफेयर्स मिनिस्ट्री को कि रिक्वायर्स के बारे में आप की क्या राय है। ऐक्सटरनल एफेयर्स मिनिस्ट्री का जवाब आता है। उस के ऊपर 11 तारीख को वह जवाब देते हैं :

"The External Affairs Ministry advised my Department that they were not aware of any demand for the recall of Shri A. M. Thomas."

अब विदेश मंत्री कौन है ? यह जो बैठी हुई है वह विदेश मंत्री भी है और प्रधान मंत्री भी है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार ही नहीं रह गयी है। यह बिलकुल खंडित सरकार है।

श्री कान्हाजीत खादब (आजमगढ़) : अब से बोलिये। 'है' की जगह 'हैं' कहना सीख लीजिये।

श्री मधु लिमये : हिन्दी को हम ज्यादा सिम्पलीफाई करना चाहते हैं और पूरी तरह राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं। जो मैं हिन्दी बोलता हूँ वह राष्ट्रभाषा हिन्दी है। हो सकता है कि वह आप की हिन्दी न हो। लेकिन मैं यह साफ़ कर देना चाहता हूँ कि मैं बिलकुल अब के साथ बोल रहा हूँ। जो प्रधान मंत्री है वही विदेश मंत्री है। अब प्रधान मंत्री का

सेक्रेटेरियट विदेश मन्त्रालय को नहीं बतलाता है और विदेश मन्त्रालय जगजीवन राम जी को नहीं बतलाता है यह बात सही है कि तारीख को जगजीवन राम जी को नीचा दिखाया गया और इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि मेरे प्रश्न का जवाब प्रधान मन्त्री जी दें कि 16 फरवरी को मेरे पत्र द्वारा नोटिस मिलने के पश्चात् और 30 मार्च को इनका कमेंट आने के पश्चात् भी आपने विदेश मन्त्रालय और खाद्य मन्त्रालय की टीमस साहब के रिक्वायर्स के बारे में जानकारी आप ने क्यों नहीं दी ? क्या प्रधान मन्त्री जी इस का उत्तर देंगी ?

MR. SPEAKER : Shri George Fernandes.

श्री मधु लिमये : मेरे प्रश्न का उत्तर पहले दिलवाया जाय।

MR. SPEAKER : Whatever the points you have both of you may say. Does the Food Minister want to reply ?

श्री मधु लिमये : पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दिया जाय। उस उत्तर में से उन का क्वेश्चन निकल सकता है।

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : The first point was this. The hon. Member has said that the manner in which the file was called by the then Deputy Minister was unusual. I have said that there is nothing unusual about it. When a case is put up before a Minister or Deputy Minister it has to pass through certain channels, That is the usual thing. It goes to Deputy Secretary, to Joint Secretary to Secretary and then to the Minister or Deputy Minister, as the case may be. That is the usual channel. But when a Minister or a Deputy Minister wants to see certain papers he calls from wherever the paper is and it is not necessary that it passes through all these channels.

श्री मधु लिमये : यह मेरा सवाल नहीं है। मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाय।

**SHRI JAGJIWAN RAM :** There is nothing unusual for the Minister or Deputy Minister calling for any paper from any Department under him. That is what he did. What has Mr. Thomas done ? He wanted to see whether certain thing was done with a view to prevent defrauding the Government in case of short supply of rice or short landing of rice. He wanted to know what the Department was doing about it. The file was called for. He found in the file that precautionary action was being taken. There was nothing for him to indicate on the file. He saw the file. He was satisfied with the action that was being taken and then the file was returned. There is no case for calling for any explanation from Mr. Thomas or even enquire from him.

**SHRI VASUDEVAN NAIR (Peermade):** Is it true that the local representative of Apeejay lines is also another Thomas in Delhi ?

**SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur) :** All Sharma's are not related to each other!

**SHRI JAGJIWAN RAM :** So far as the Prime Minister was concerned, as I have stated in the statement and clarification itself...

**श्री मधु लिमये :** इसी लिये प्रधान मन्त्री से सुनना चाहते हैं, आप से पूछना ही नहीं है।

**SHRI JAGJIWAN RAM :** I think that clarification is quite satisfactory and nothing further is required.

**श्री मधु लिमये :** इस तरह से तो मैं नहीं चलने दूंगा।

**MR. SPEAKER :** Let the hon. Minister complete what he wants to say.

**SHRI MADHU LIMAYE :** I am satisfied with his explanation. I want an answer from the Prime Minister.

**SHRI JAGJIWAN RAM :** Therefore, I had said that everything was quite clear and there was nothing to ascertain from Shri A. M. Thomas, and, therefore, it was thought that that clarification was quite satisfactory.

**श्री मधु लिमये :** क्या मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आयेगा ? मैं ने उन से पूछा ही नहीं था। मैं अपना प्रश्न फिर रिपीट करता हूँ।

**MR. SPEAKER :** I allowed this under the item 'clarification from the Food Minister'. This item had not been admitted for clarification from the Prime Minister.

**श्री मधु लिमये :** वह तो ट्रांस्फर किया गया है। उस में मेरा क्या बस है ? मेरा प्रश्न तो उन्हीं के नाम से था।

**MR. SPEAKER :** If the Prime Minister can answer, that is a different matter. But the item in the agenda relates to the Food Minister.

**श्री मधु लिमये :** प्राइम मिनिस्टर के नाम से बुधवार को प्रश्न प्रकाशित हो चुका है।

**THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI) :** As my colleague the Food Minister has stated, the demand for the recall of Mr. Thomas was based on the theory that something was wrong. Once I got the explanation from the Food Ministry, the occasion for recall was not their, and I am under no obligation to inform either the External Affairs or anybody else about this matter unless the case had been made for such a recall.

**श्री मधु लिमये :** माफ कीजिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है और बहुत गम्भीर प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। आप जरा मेरे प्रश्न को देख लीजिये। इस तरह से तो उन्होंने सारे सदन का अपमान किया है। वह कहती है कि यह उन का आब्लिगेशन नहीं है। जो आप के द्वारा ऐडमिटेड क्वेश्चन था वह उन के नाम से था। उस का एक हिस्सा था :

"Whether a demand has been made for his recall in view of the suspicious circumstances, and if so, the reaction of the Government thereto."

यह मेरा प्रश्न एडमिटेड है। उन्होंने अपने नाम से ट्रांसफर किया खाद्य मन्त्री के नाम में। अब वह कहती हैं कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : नहीं, नहीं...

श्री मधु लिमये : आप ने यह कहा है। मुझे अपना प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पूरा करने दीजिये। अध्यक्ष महोदय, यह प्रधान मन्त्री हैं। औरत के नाते मैं उन की बड़ी इज्जत करता हूँ। लेकिन आप मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर सुन लीजिये।

MR. SPEAKER : Let him come to the point of order now. I find that he is reading out something else.

श्री मधु लिमये : यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। उन्होंने कहा कि कोई आब्लिगेशन नहीं है। प्रधान मन्त्री के नाम से प्रश्न या इन्फार्मेशन सप्लाई करने के लिये और आप ने उसे स्वीकार किया है।

"It is the duty of the External Affairs Minister or the Prime Minister to supply the information."

यह आप का उस दिन का वाक्य है। खाद्य मन्त्री जी ने कहा है :

"Our comments were duly sent to the Prime Minister on 30th March, 1968."

और उस के बाद एक्स्ट्रानल अफेयर्स मिनिस्ट्री से पूछते हैं।

"That Ministry advised my Department that they were not aware of any demand for the recall of Shri A. M. Thomas."

MR. SPEAKER : What is the point of order ? Let him state it now.

श्री मधु लिमये : मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि 30 मार्च और 11 अप्रैल के बीच में अपना निर्णय, अपना उत्तर और उन के पास जो जानकारी थी उसे खाद्य मन्त्री के जवाब के

लिये देना उन का कर्तव्य था। अब वह कह रही हैं कि :

"I am under no obligation."

मैं जानना चाहता हूँ कि इस न में कोई अधिकार है या नहीं ?

SHRI RANGA (Srikakulam) : Is it a point of order ?

श्री मधु लिमये : हमारे कुछ अधिकार हैं या नहीं ? मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा ?

SHRI RANGA : Before you express your view regarding this point of order, you will have to give some consideration to the way in which we have to deal with this Government and this House has to deal with this Government. Here is the Prime Minister who is above all these various things...

MR. SPEAKER : Does he want a discussion on the point of order now.

SHRI RANGA : This is a very important matter.

MR. SPEAKER : A point of order has been raised, and I have to give my ruling on it.

SHRI RANGA : Excuse me, Sir...

MR. SPEAKER : I do not know what to do ; if the leader of a party says like this, what can I say ? It is a point of order which he has raised. Does he want a discussion on the point of order ?

SHRI RANGA : On the point of order, I want to make my submission.

MR. SPEAKER : If Shri Ranga, the leader of the Swatantra Party here says that every point of order must be discussed, then I cannot resist it. When a point of order is raised, I think the Speaker has to give his ruling on it. There cannot be a discussion on the point of order.

SHRI NATH PAI (Rajapur) : Others can also put in their plea.

SHRI RANGA : I do not wish to argue with you. But what I have understood always in regard to a point of order is that such of the other Members as feel like strengthening or opposing the point of order are entitled to draw your attention to certain points. Thereafter, you may be pleased either to uphold the point of order or to dismiss it.

MR. SPEAKER : That means when a point of order is raised by some Member, we will have to hear everybody else here.

श्री मधु लिमये : यह महत्वपूर्ण बात है।  
श्रम सुन लीजिये।

SHRI RANGA : You may exercise your judgment, after you allow two or three members, when you think there has been sufficient clarification of the issue involved.

MR. SPEAKER : I would ask him to consider how he would limit the discussion to two or three members if he were in my position. Otherwise, I do not mind.

SHRI RANGA : Surely two or three of us who are Leaders of the Opposition Parties could be heard.

MR. SPEAKER : Shri D. C. Sharma is already getting up.

SHRI RANGA : That way you can always prevent us from saying anything on the ground that 'other people will also want to speak, so please keep quite.' That is the not way we can carry on here. I do not wish to trouble you. But I would only say this that I would like the Prime Minister to take counsel with her own colleagues and constitutional advisers also later on to realise that what she has said this morning is not the right thing, is not the correct thing, is not within the four corners of constitutional propriety. I do not wish to say anything more.

SHRI MADHU LIMAYE : Under rule 376, Shri Ranga has a right of say.

SHRI D. C. SHARMA : A point of order is essentially between a Member of the House raising it and the Speaker or the hon. Member who sits in your Chair by

your permission. I do not know what right any other Member has, even if he be the leader of an Opposition Party, to amplify or magnify it or to put a kind of gloss on it. I think the Food Minister has made the position very clear and the Prime Minister has said that there is no point of order in it. I think we are trying to take out water from something out of which nothing can be got. The point of order deserves to be treated with the utmost contempt and indifference.

SHRI NATH PAI : May I humbly make a submission? I am not trying to go into the substance of the matter raised by Shri Limaye. In the first place, for future guidance of the House, let us turn to page 113 of *More*, where he says that when there is a point of order, there cannot be a point of order on that point of order, as the learned Professor was trying to raise. Let us now turn to our rule 376(4):

"...the Speaker may,

SHRI JAGJIWAN RAM : If he wants the assistance of any member...

SHRI NATH PAI : I wish his other colleagues know the rules as he knows.

MR. SPEAKER : I thought I had heard the member who raised the point of order. Is he also raising a point of order?

SHRI NATH PAI : I am supporting Shri Limaye's point of order.

MR. SPEAKER : If we allow this kind of thing, tomorrow it will come in our throat every time.

SHRI NATH PAI : No, Sir.

MR. SPEAKER : I do not mind it. I am only saying that this will be the result.

SHRI RANGA : You can always put a stop somewhere, but you cannot put a stop to the leaders of groups.

SHRI NATH PAI : I am repeating that when there is a point of order, there can not be a second point of order. I am

rising in support of the point of order raised by Shri Limaye.

Perhaps the Prime Minister did not intend to say what she said. She has allowed herself to say, she has permitted herself to say, something which is highly derogatory to this House (*Interruptions*).

SHRIMATI INDIRA GANDHI: No, no (*Interruptions*). There is a misunderstanding.

SHRI NATH PAI: She said 'I am under no obligation to give...

SHRIMATI INDIRA GANDHI *rose*—

श्री मधु लिमये : पूरे सदन के सामने कहा है। अब क्लैरिफाई कर रही हैं।

SHRI NATH PAI: I am glad that she wants to clarify. I will continue after her. (*Interruption*).

SHRIMATI INDIRA GANDHI *rose*—

SHRI NATH PAI: A Member who is in possession of the House and is making his point of order must sit down voluntarily and you must ask for his leave.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: I am sorry.

SHRI NATH PAI: You may kindly continue.

SHRI MADHU LIMAYE: Now, she will sweetly smile and everything will be over!

SHRIMATI INDIRA GANDHI: I am sorry if there is some misapprehension about what I said. I did use the word "obligation". I am not saying that I did not use it. But I did not use it in connection with the hon. House. (*Interruption*) I was talking about the External Affairs Ministry. The question was whether I had sent that to the External Affairs Ministry. That is what I am saying. (*Interruption*).

SHRI RANGA: We gave you an opportunity for consulting your advisers before you come to a decision.

श्री मधु लिमये : विदेश मन्त्री आप हैं और प्रधान मन्त्री भी आप हैं। प्रधान मन्त्री

का कार्यालय विदेश मन्त्रालय को बताता नहीं है। यह अच्छा तमाशा चल रहा है। इसको गवर्नमेंट आफ इंडिया कहते हैं।

SHRI RANGA: From the External Affairs Ministry, they sent it to the Agriculture Ministry. But the Agriculture Ministry says "we do not have the information". But here comes the Prime Minister and says "I am under no obligation to inform the Agriculture Ministry about the External Affairs Ministry."

Then, where is the Prime Minister going to function, in the sky, or in a vacuum or by herself, throwing a thunderbolt on Parliament as well as on the other Ministry? It is again an extraordinary position to take for the Prime Minister.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER: Order, order. Once or twice, I would certainly like to hear the leaders and other Members, but if every minute they get up what should I do? I can only be helplessly sitting; that is all. I can understand once or twice, but if every minute this is done, you are not helping the Chair to conduct the proceedings of the House and I will become helpless. I can understand if some Members or some leaders of parties get up; I can hear them, say Shri Ranga or Shri Vajpayee and others. Whatever the wretched rule may say, when a leader of a Party gets up, we have to give him a little consideration. But if every minute they get up, what am I to do? I do not know what I should do. Will you complete now, Mr. Nath Pai?

SHRI NATH PAI: Mr. Speaker, Sir, I am glad that the hon. Prime Minister made partial amends; but I expected full amends. Now, Sir, if you are patient with me, I shall finish quickly. I am not in the habit of saying what is irrelevant. It says that "the Ministry advised my department that they were not aware of any demand for the recall of Shri A. M. Thomas." This is quite in contradiction of what para 2 says. It was in this connection that and explanation was required and whether the time allowed to her was insufficient. It was while explaining this that she allowed herself to say something which I hold... (*Interruption*).

MR. SPEAKER : What is the point of order ?

SHRI NATH PAI : I am coming to it. Neither the Prime Minister nor Shri Madhu Limaye nor I have got a right to take a position with regard to Parliament whereby it appears that we do not recognise its authority. When the Prime Minister said "I am not under any obligation", this was nothing short of—not deliberately—inadvertence perhaps. But nonetheless, even so, it was a remark which was unfortunate to say that "I am under no obligation. She is under every obligation to this House to give an explanation when called upon. Since the remark was unwittingly uttered by her, it should be gracefully withdrawn by her. (Interruption).

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER : She explained it later ; she said it is not in connection with the House at all. (Interruption).

श्रीमती इन्द्रा गांधी : मुझे एक पत्र लिखा गया। इसका सम्बन्ध एपीजे की कुछ-बातों से था। चूंकि खाद्य मन्त्रालय का संबंध इससे था इसलिए जो उसका रिलेबेंट पैरा था वह उनको भेजा गया। यह जो इन्होंने दूसरी डिमांड की है उसका जिक्र न तो इन से किया गया और न दूसरे मन्त्रालय से किया गया।

जब मुख्य विषय के बारे में जवाब आया तो मुझे लगा कि इस विषय में और कुछ नहीं करना है। मैंने निर्णय लेने में कोई देर नहीं की। मैंने निर्णय ले लिया कि श्री टामस को वापिस नहीं बुलाना है। इसलिए उसके सम्बन्ध में मैंने कहा है कि यह दूसरी बात मैंने एक्स-टर्नल एपेयज से नहीं कही थी।

जहां तक इस सदन का प्रश्न है इस में कोई दो रायें हो ही नहीं सकती हैं और मैं कभी न तो कह सकती हूँ और न ही सोच सकती हूँ कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तो पूरी है।

अध्यक्ष महोदय ; श्री फर्नेंडीज ।

SHRI MADHU LIMAYE *rose*—

MR. SPEAKER : I have called Mr. Fernandes.

SHRI MADHU LIMAYE : You give a ruling on my point of order.

MR. SPEAKER : I have not accepted the point of order.

श्री फर्नेंडीज : यह जो प्रश्न है यह दस अप्रैल को प्रधान मंत्री के नाम पर था। और प्रधान मंत्री के नाम पर प्रधान मंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि विदेश मंत्री की हैसियत से तो था। प्रश्न का उत्तर अन्न मंत्री ने दे दिया। चूंकि दोनों से इसका सम्बन्ध है, इसलिए मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे रहा हूँ। दस अप्रैल को प्रधान मंत्री को इस प्रश्न का जवाब देना था। लेकिन ग्यारह अप्रैल को यानी एक दिन के बाद अन्न मंत्री ने इसका जवाब दे दिया। यह जो प्रश्न ट्रांसफर हुआ मैं समझता हूँ कि दस तारीख को ही हुआ चूंकि दस तारीख के नोटिस पेपर में यह आया था। यह दस तारीख को ट्रांसफर हो गया। मैं समझता हूँ कि दस तारीख को इसका उत्तर देने के लिए प्रधान मंत्री जी ने भी जरूर तैयारी की थी। प्रश्न के दूसरे हिस्से में पूछा गया था और उनके रिकाल की मांग की गई थी। यह कहा गया था :

"whether he has been sent to Australia as our High Commissioner ; whether an attempt has been made for his recall in view of the suspicious circumstances and if so, the reaction of the Government thereto".

मैं समझता हूँ कि दस तारीख तक प्रधान मंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर तैयार करके रख लिया होगा, अगर वह अपना काम करती होतीं तो। ग्यारह तारीख को अन्न मंत्री जी ने उत्तर दिया। फिर यहां से यह सारा भ्रष्ट शुरु हुआ। यह कहते हैं कि एक्सटर्नल मन्त्रालय से हमें कोई इसका पता नहीं चला। अब आप देखें कि दस



तारीख को प्रधान मंत्री की ओर से उत्तर आना था और ग्यारह तारीख को अन्न मंत्री जी इसका जवाब देते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री का तैयार किया उत्तर रिकॉल के बारे में क्या अन्न मंत्री को बतलाने में नहीं आया ?

आपने यह कहा है कि मैंने एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्ट्री से पूछताछ की और एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्ट्री ने हम से यह कहा कि हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। हो सकता है कि प्रधान मंत्री के नाम की कुछ गड़बड़ी के कारण यहां मन्त्रालयों में भी गड़बड़ होती हो। यह मुझे मालूम नहीं है। बर्ना प्रधान मंत्री एक्सटर्नल एफेयर्स मंत्री भी हों तो मेरी समझ में नहीं आता है कि किस तरह से वह कह सकती है कि मुझे यह मालूम नहीं है कि ऐसी कोई मांग हुई है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस तारीख के उत्तर का आपको पता था और आपके द्वारा प्रधान मंत्री की ओर से एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्टर की हैसियत से उस उत्तर को भेजने का काम हुआ था या नहीं हुआ था।

फूड मिनिस्टर की स्टेटमेंट का आखिरी हिस्सा आपने देखा ही होगा।

"I would like to state that after full consideration of the matter, the Government are satisfied that no action is necessary on the suggestion made by Mr. Limaye for therecall of Mr. A. M. Thomas."

अन्न मंत्री विदेश मंत्री की ओर से हमें उत्तर दे कर कह रहे हैं कि उनको वापिस बुलाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। यह फंसला हो सकता है कि विदेश विषयक मंत्री ने लिया हो या प्रधान मंत्री ने लिया हो लेकिन निश्चित तौर से अन्न मंत्री यह फंसला नहीं ले सकते थे टामस साहब के बारे में। मैं जानना चाहता हूँ कि श्री मधु लिमिये का पत्र जाने के बाद आप लोगों ने कोई पूछताछ की है और की है तो क्या खुलासा उनकी ओर से आया है ?

SHRI JAGJIWAN RAM : So far as the last portion is concerned, I have already answered it. Only the question was transferred to my Ministry. There was no draft reply to that. Therefore, it was necessary to ascertain that portion, as I explained in my statement, whether something was there in the External Affairs Ministry. As explained in my statement and also by the Prime Minister, the reply that was received from External Affairs was given to the House.

As I have already stated, there is no case for ascertaining anything from Shri Thomas. It was quite clear, as I have explained. Shri Thomas might have read in the papers. He was not informed of this because there was no necessity for that.

MR. SPEAKER : Before adjourning the House for lunch.....

श्री जार्ज फरनेन्डीज : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरी बात सुनिये।

13.00 hrs.

#### BUSINESS OF THE HOUSE

MR. SPEAKER : The hon. Member may resume his seat. I am on my legs. What I want to say is this. The Business Advisory Committee has decided only two hours for discussing the Demands for Grants relating to the Ministry of Industrial Development and Company Affairs. My difficulty is, when only one hour or two hours time is allotted for a particular Ministry I am not able to give half-an-hour to each hon. Member. For the discussion on the Demands for Grants relating to Social Welfare, according to the wishes of many hon. Members of this House, three hours have been allotted—from 4.00 to 7.00 P. M. today. Today is the last day as far as Demands for Grants are concerned. We have to apply guillotine at 7.00 P.M. and from 4.00 to 7.00 we have to discuss Social Welfare. Therefore we have only two hours for Industrial Department and Company Affairs. If all the parties want to speak I cannot deny time to one party and give half-an-hour to another party,